**श्री हरदयाल देवगुण** : श्रीमन्, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह पटसन, दालें और जो चीजें यहां से बाहर जाती हैं जिन के बारे में बार-बार पूछा गया है इन का और चीन से जो माल आता है इन का क्या संबंध है और इस सारी स्मगिलंग को रोकने के लिये सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है । हर एक प्रश्न में बता दिया जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं । लेकिन एक-एक कर के यह मालूम होता है कि स्मगिलंग बढ़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है । अगर नहीं कर रही है तो त्यागपत्र दे दे ।

**श्री मोरारजी देसाई** : त्यागपत्र मांगने का सम्मानित सदस्य को सब जगह तो अधिकार नहीं है । यह हाउस का जरूर है·····

**श्री हरदयाल देवगुण** : यह हाउस में ही मांग रहे हैं ।

**श्री मोरारजी देसाई** : अकेले मांगने से कुछ नहीं होगा·····

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : हम भी साथ में हैं·····(**व्यवधान**)·····

**श्री मोरारजी देसाई** : आप चार-पांच, पचास मांगेंगे तो भी कुछ नहीं होता । मेजारिटी मांगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा ।

मैंने डी में इसकी तफसील दी है । सम्मानित सदस्य उस को सुनते नहीं हैं तो हम क्या करें ?

**जापान के सहयोग से उद्योगों की स्थापना**

*515. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के उद्योग मंत्री ने केरल में उद्योग स्थापित करने के लिये जापान की कुछ फर्मों के साथ करार करने के उद्देश्य से हाल में जापान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस की अनुमति दी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या रवैया है ?

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). हालांकि यात्रा की अनुमति उन प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये दी गई थी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार सिद्धान्त रूप से मंजूरी दे चुकी थी, लेकिन अनुमति देते समय यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि तकनीकी सहयोग की शर्तों के अन्तिम रूप से तय किये जाने से पहले, इनके लिये केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक होगा और सारी बातचीत इस शर्त के साथ की जानी चाहिये ।

**श्री मोहन स्वरूप** : आज देश में प्रवृत्ति इस तरह की हो रही है कि चारों तरफ अलगाव की भावना बढ़ रही है । यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है—इस के पहले भी एक बार पैरादीप पोर्ट के सिलसिले में जापान ने यहां की सरकार के साथ बात की थी, अब फिर इस तरह की बात सामने आई है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि इस तरह से राज्यों को स्वतन्त्रता दे दी जाये कि वे अपनी तरफ से बाहर के देशों से बात करें—क्या यह देश के लिये घातक सिद्ध नहीं हो सकता है ? इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये आगे क्या कदम उठाये जायेंगे ?

**श्री मोरारजी देसाई** : उन को जिन शर्तों पर बात करने की अनुमति दी गई थी, वह अभी बताई गई हैं । यदि इन शर्तों पर उन्होंने बात नहीं की और दूसरी बातें की होंगी, तो इस से नुक्सान उन मंत्री को होगा, राज्य को नहीं होगा ।

**श्री मोहन स्वरूप** : मैंने पूछा था कि भविष्य में इस के लिये क्या रोकथाम करेंगे ?

**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने कहा है कि उन को माना नहीं जायेगा । यही उसकी सब से बड़ी रुकावट होगी, इस के लिये और दूसरी रुकावट क्या चाहिये ?

**श्री मो० प्र० त्यागी** : जापान ने अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, अपने यहां छोटे उद्योगों को अधिक महत्व दिया है । भारतवर्ष की भी यही समस्या है, क्या इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जापान के इस अनुभव का लाभ उठाने की चेष्टा की है कि यहां भी छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय ?

**श्री मोरारजी देसाई** : उस का भी ध्यान किया जाता है और इस सिलसिले में भी कुछ न कुछ काम किया गया है ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : The hon. member, Shri Mohan Swarup, put a very fundamental question, whether the State Governments, may be with the permission of the Central Government, can carry on negotiations with foreign governments for collaboration and aid. May I know whether this is in consonance with the federal character of our Constitution and this will not lead to disintegration of the country and, if so, whether Government is going to lay down a firm policy to see that whatever negotiations are to be carried on with foreign countries, they are carried on by the Central Government alone ?

SHRI MORARJI DESAI : I have already explained that these negotiations which are carried on by any State minister can be carried on only within the limits of the permission given by the Government of India. Any other negotiations which are carried on by them will be invalid and no action will be taken on them. They cannot make anything final.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : But you allow them to go and negotiate.

SHRI MORARJI DESAI : Yes; we allow them to go out only for schemes which have been agreed to by the Government of India and not for other schemes.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : You can send your representative.

SHRI MORARJI DESAI : If private parties can negotiate with other private parties in foreign countries with the approval of this Government, I do not see why State Governments cannot carry on negotiations with another Government within the limits prescribed for that. Surely, the State Governments should not have less rights than a private individual.

**श्री स० मो० बनर्जी** : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री अभी जापान गये थे, उस समय क्या कुछ ऐसी बातें हुई थीं कि जापान की कुछ प्राइवेट और सरकारी फर्में इस बारे में इन्टरस्टेड हैं कि हमारे देश में कुछ उद्योग लगायें ? यदि हुई थीं, तो सरकार की उन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने किसी खास उद्योग के लगाये जाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी, मैंने तो यह प्रयत्न किया कि जिससे हमारे सामान्य सम्बन्ध अच्छे बनें, और वहां के लोग यहां आना चाहें, तो आयें । यही बात हुई थी, किसी खास उद्योग के बारे में बात नहीं हुई थी ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मुझे उप-प्रधान मंत्री के इस उत्तर को सुन कर ताज्जुब हुआ । जो काम प्राइवेट कम्पनीज़ कर सकती हैं, उस को करने के लिये मुख्य मंत्री को छूट क्यों नहीं होनी चाहिये । मेरा निवेदन है कि प्राइवेट पार्टियां केवल कम्पनी को बांधती हैं, जब कि मुख्य मंत्री अपने प्रदेश के शासन को बांधता है, कुछ हद तक देश को बांधता है । उप प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम जो शर्तें तय करते हैं, उन शर्तों के आधार पर वह समझौता कर सकते हैं । अगर उन शर्तों पर समझौता नहीं करेंगे तो वह समझौता नहीं माना जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उप-प्रधान मंत्री यह स्वीकार नहीं करते कि इस तरह से—वह समझौता कर के आये और फिर उस को न माना जाय—देश के सामने कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं ? क्या यह सम्भव नहीं है कि जब इस तरह मुख्य मंत्री बातचीत करने के लिये जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि या वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि भी उन के साथ जाये ताकि इस तरह से भविष्य में कोई कठिनाई पैदा न हो ?

**श्री मोरारजी देसाई** : जो शंका सम्माननीय सदस्य ने उठाई है, वह शंका हो सकती है। परन्तु मुख्य मंत्री तो नहीं गये थे, यहां तो उद्योग मंत्री गये थे। अब उद्योग मंत्री जायें और उन के साथ किसी को भेजें....

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : उन की मदद के लिये भेजें।

**श्री मोरारजी देसाई** : अगर उन को जरूरत हो तो भेजें, लेकिन वह मदद न मांगे तो क्यों भेजें। जब ऐसी हालत मालूम होगी कि उन्होंने शर्तों के बाहर कुछ किया है, तो हम उस को नामंजूर कर देंगे, और दूसरी बार उन को नहीं भेजेंगे।

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : Mr. Speaker, Sir, as far as Kerala is concerned neither private industrialists go there to start industries nor the Government of India sanctions more industries for Kerala. I would like to ask, when private persons, as agreed to by the hon. Deputy Prime Minister, negotiate with foreign firms, go abroad and bring some contracts and the Government of India gives clearance for starting those industries, what is the harm in permitting the State Government to set up small-scale industries, to solve the unemployment problem, beyond the Five Year Plan and with the clearance of the Government of India ?

SHRI MORARJI DESAI : Where have I objected to it ? If they can find money they can start anything they like.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : Will you be standing in the way if they get any foreign loan from governments of other countries ?

SHRI MORARJI DESAI : I shall certainly prevent them from doing so if they do so without my approval.

SHRI S. KUNDU : Sir, of the many visits abroad of the Deputy Prime Minister, one was to Japan. In the statement laid before the House he has said that he met some businessmen in Japan and also some politicians. He has further said that the meeting was useful. I would like to know precisely whether there were any concrete business projects with collaboration drawn up during his visit and meeting with businessmen and politicians in Japan ?

SHRI MORARJI DESAI : I have said very clearly that no such specific proposals were ever considered or discussed. There was therefore no question of any finalisation. It was only in general terms that discussion took place. They wanted to understand several policy matters and conditions in this country. I wanted to understand what was going on there and what was troubling them. They wanted to know what was troubling us. These are the things which we discussed and on which we had an understanding.

SHRI S. S. KOTHARI : What is the Government's attitude to collaborations in small and medium scale industries with Japanese counterparts just as they have in large-scale industries ?

SHRI MORARJI DESAI : The same policy will apply. If the collaboration is necessary and useful, it will be allowed.

## SHORT NOTICE QUESTION

### बरौनी तेल शोधक कारखाने के इंजीनियर

**SNQ 10. श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने ने अपने तेल शोधक कारखाने के निर्माण खण्ड में काम करने-वाले ३५ इंजीनियरों को छंटनी का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छंटनी किये गये इंजीनियरों में कितने इंजीनियर बिहार के हैं तथा कितने अन्य राज्यों के ?

**पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं।